ई संदेश

20 नवंबर 2025|अंक 180

सात दिन-सात पृष्ठ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लोकनायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजाति भागीदारी उत्सव में समारोह को आह्लादित करते हुए

जनजातीय समुदाय के लोगों ने सदैव भारत की विरासत व धरोहर को संरक्षित करने का कार्य किया: मुख्यमंत्री

केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वीरांगना ऊदा देवी पासी जी के बलिदान दिवस पर किया सम्मान और समारोह

प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के लिए मिलकर कार्य कर रहे: मुख्यमंत्री

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जनजातीय समुदाय तेजी से आगे बढ़ रहा तथा देश के विकास में अपना योगदान दे रहा: मुख्यमंत्री

दीक्षांत समारोह भारत की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के समावर्तन समारोह का परिवर्तित रूप: मुख्यमंत्री

फॉरेन्सिक लैब मॉडर्न पुलिसिंग के लिए गेम चेंजर साबित होगी : मुख्यमंत्री

प्रदेश के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों को समयबद्ध सिंचाई उपलब्ध कराने की दिशा में नई स्वीकृत परियोजनाएं महत्वपूर्ण : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 14 नवम्बर, 2025 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

जनजातीय समुदाय के लोगों ने सदैव भारत की विरासत व धरोहर को संरक्षित करने का कार्य किया: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 12 नवंबर 2025 को यहां लखनऊ में लोकनायक 'धरती आबा' भगवान बिरसा मुण्डा की 150वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जनजातीय समुदाय के अतुलनीय योगदान को समर्पित जनजाति भागीदारी उत्सव (13 से 18 नवम्बर, 2025) का शुभारम्भ किया।

समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भगवान बिरसा मुण्डा की विरासत राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिक सौहार्द को बनाये रखने की प्रेरणा प्रदान करती है। भगवान बिरसा मुण्डा धरती माता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करने हेतु किये जाने वाले संघर्ष के प्रतीक हैं। जनजातीय समुदाय के लोगों ने सदैव समाज के अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर भारत की विरासत व धरोहर को संरक्षित करने का कार्य किया है। डबल इंजन सरकार जनजातीय गौरव की पुनर्स्थापना करते हुए जनजातीय समाज के कल्याण के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। जनजातीय समाज व उनकी विरासत के संरक्षण हेतु उन्हें प्रत्येक प्रकार का सहयोग व समर्थन प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जनजातीय समुदाय को अपनी परम्परा, संस्कृति और विरासत पर गौरव की अनुभूति कराने, समाज व राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ कर सम्मान के साथ आगे बढ़ने का बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश में 01 नवम्बर से 15 नवम्बर, 2025 तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। 'धरती आबा' भगवान बिरसा मुण्डा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के उद्देश्य से यहां जनजाति भागीदारी उत्सव आयोजित किया जा रहा है।

इस उत्सव में देश के 22 राज्यों से आए जनजातीय समुदाय के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक समागम एवं यात्रा के अन्तर्गत जनजातीय संस्कृति एवं परम्पराओं का प्रदर्शन किया जाएगा।

केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वीरांगना ऊदा देवी पासी जी के बलिदान दिवस पर किया सम्मान और समारोह

केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 16 नवम्बर, 2025 को यहां लखनऊ में शौर्य, त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति वीरांगना ऊदा देवी पासी जी के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा का अनावरण, उनके परिजनों का सम्मान तथा स्वाभिमान समारोह का उद्घाटन किया।

केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि वीरांगना ऊदा देवी ने न केवल अदम्य साहस व पराक्रम से अंग्रेजी सेना को धूल चटाई बल्कि राष्ट्र प्रेम का ऐसा मानक स्थापित किया, जो अनन्त काल तक भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रेरणा देता रहेगा। लखनऊ के पास अंग्रेजों से लड़ते हुए जब वीरांगना ऊदा देवी के पति मक्का पासी शहीद हुए, तब उन्होंने हिम्मत हारने के बजाय पति की शहादत का बदला लेने का संकल्प किया।रक्षा मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश को विकास की अप्रतिम ऊंचाई प्रदान की है। मुख्यमंत्री जी ने पासी समाज के वीरों और वीरांगनाओं को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने का अभूतपूर्व फैसला लिया है। वह ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जो सर्व समाज के कल्याण के लिए किसी भी हद तक जाकर कार्य करते हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि वीरांगना ऊदा देवी का बलिदान दिवस वर्तमान पीढ़ी को राष्ट्रीयता के साथ जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। नारी शक्ति का सम्मान तथा वंचित वर्ग का उत्थान डबल इंजन सरकार का मुख्य ध्येय है। वीरांगना ऊदा देवी नारी शक्ति के सामर्थ्य का स्मरण कराती हैं। ऐसी वीरांगनाओं का बलिदान हम सभी को प्रेरणा प्रदान करता है। भारत को स्वाधीन कराने में वीरांगना ऊदा देवी जैसी वीरांगनाओं व वीरों का अतुलनीय योगदान रहा है।

वीरांगना ऊदा देवी न केवल नारी जाति के लिए, बल्कि प्रत्येक हिंदुस्तानी के लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने विदेशी हुकूमत के अत्याचार का जवाब देने के लिए 16 नवम्बर, 1857 को लखनऊ के सिकंदर बाग में पीपल के वृक्ष पर चढ़कर अंग्रेज सैनिकों को ढेर कर दिया। इससे उनका नाम भारत के इतिहास में अमर हो गया। ऊदा देवी का बलिदान प्रेरणा देता है कि यदि अन्याय बड़ा हो तो प्रतिरोध उससे भी बड़ा होना चाहिए। उन्होंने उस समय देश के युवाओं को अन्याय का सामना करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार प्रदेश में विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। काशी में श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर तथा अयोध्या में श्रीरामलला मंदिर का निर्माण हो चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में महाराजा बिजली पासी के किले का सुन्दरीकरण किया गया है। महाराजा बिजली पासी किले में लाइट एण्ड साउण्ड की व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महाराजा लाखन पासी, महाराजा सातन पासी, महाराजा बिजली पासी, महाराजा छीता पासी, राजा गंगा बक्श रावत और महाराजा वीरा पासी के इतिहास से वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराने के लिए प्रदेश सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा इस सम्पूर्ण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए क्रांतिकारियों, बलिदानियों व भारत माता के अमर सपूतां के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बच्चों को एक अतिरिक्त पुस्तक उपलब्ध कराई गई है, जो क्षेत्रीय, जनपद व प्रदेश स्तर पर महापुरुषों के योगदान के बारे में वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराएगी। प्रदेश सरकार द्वारा पी0ए0सी की तीन नई महिला बटालियनों का गठन सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की महान वीरांगनाओं के नाम पर किया गया है।

लखनऊ की बटालियन का नाम वीरांगना ऊदा देवी के नाम पर रखा गया है। गोरखपुर में गठित महिला बटालियन का नामकरण वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर किया गया है।बदायूं में गठित बटालियन का नाम वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर किया गया है। तीनों वीरांगनाओं ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में नारी शक्ति के पराक्रम व शौर्य को फिरंगियों के सामने प्रस्तुत कर, उन्हें धूल चटाने का कार्य किया था। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा व्यवस्था में दी जा रही सुविधाओं,लाभों तथा स्कॉलरशिप योजनाओं के बारे में भी बताया।

प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के लिए मिलकर कार्य कर रहे: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत 16 नवंबर, 2025 को यहां लखनऊ में 'उत्तराखण्ड महोत्सव-2025' में सम्मिलित हुए। उन्होंने 'उत्तराखण्ड दर्पण स्मारिका' तथा 'उत्तराखण्ड महोत्सव कैलेण्डर' का विमोचन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि यह महोत्सव केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, अपितु दो संस्कृतियों के मिलन के साथ उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को लखनऊ की इस धरती पर जीवित और संजोकर रखने का प्रयास भी है।केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि भारत सरकार के अनुरोध पर यूनेस्को ने लखनऊ को भोजन की उत्कृष्ट परम्पराओं का निर्वहन करने वाले शहर (क्रिएटिव सिटी ऑफ़ गैस्ट्रोनॉमी) के रूप में चयनित किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा डोजियर बनाने तथा उसे सबमिट करने सहित अन्य प्रभावी प्रयास किए गए। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए निरन्तर कार्य किए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने महोत्सव को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं। यह महोत्सव हमारी लोक परम्परा और संस्कृति को जीवन्त बनाए रखने का माध्यम है। यह महोत्सव आज की आपाधापी भरी जिंदगी में लोगों को अपनी लोक कला, लोक गायन और लोक संस्कृति से जोड़ते हैं। यह लोक गीत और लोक कला इतिहास का संरक्षण करते हैं। विदेशी इतिहासकारों ने जानबूझकर भारत के अनेक गौरवशाली क्षणों को हमारे इतिहास में शामिल नहीं किया, लेकिन लोक गायन और लोक कला के माध्यम से वह गाथाएं हमें आज भी देखने और सुनने को प्राप्त होती हैं। यह परम्पराएं हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रयासों से वर्तमान उत्तराखंड का गठन 09 नवम्बर, 2000 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पण्डित गोविन्द बल्लभ पंत जी ने प्रदेश के विकास में अपना पूरा योगदान दिया। पण्डित गोविन्द बल्लभ पंत जी द्वारा प्रदेश के विकास की जो नींव रखी गयी, उसी पर आज के उत्तर प्रदेश का निर्माण हुआ है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखण्ड में ही स्व0 हेमवती नंदन बहुगुणा जी तथा स्व0 नारायण दत्त तिवारी जी का जन्म हुआ। देश के स्वाधीनता आन्दोलन में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली का स्मरण हर देशवासी करता है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सी0डी0एस0) जनरल विपिन रावत उत्तराखण्ड की ही देन हैं। माँ गंगा, माँ यमुना, सरयू जी और शारदा जी इसी क्षेत्र से निकलकर उत्तर प्रदेश की भूमि को उपजाऊ करते हुए सोना उगलने वाली धरती के रूप में बदलने का कार्य करती हैं। इस तरह उत्तराखंड की धरती में भक्ति और शक्ति का समन्वय दिखायी देता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें अपनी मातृभूमि और देव भूमि पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। वहां की लोक कला, परंपराओं, खानपान और लोक संस्कृति को संरक्षित करने के लिए एक प्लेटफार्म देना चाहिए। यही प्रधानमंत्री जी के 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' विजन का भाव है। श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी अपने मंत्रालय के माध्यम से इसे नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखण्ड महापरिषद प्रतिवर्ष राष्ट्र, समाज एवं संस्कृति के उत्थान में अपना योगदान देने वाली विभूतियों को उत्तराखण्ड गौरव से सम्मानित करती है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब उत्तराखण्ड महापरिषद जैसी संस्थाएं देश और समाज के लिए समर्पित भाव से कार्य करने वालों और आज के समय में नवाचार और शोध को बढ़ाने वाले लोगों को सम्मानित करती हैं, तो यह स्वयं संस्था के लिए भी सम्मान का कार्य होता है। इससे नौजवानों को प्रेरणा प्राप्त होती है। हमें अपनी संस्कृति, लोक कला और लोक परम्पराओं को संरक्षित करने वाले उन कलाकारों का भी सम्मान करना चाहिए, जो पुराने वाद्य यंत्रों को नये तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखण्ड महापरिषद अपने कार्यक्रमों में निरन्तरता बनाए रखे और एकजुटता के साथ इन्हें आगे बढ़ाए। अपनी लोक कला, लोक संस्कृति तथा लोक परम्पराओं को आगे बढ़ाने का लाभ पूरे देश को मिलेगा। यह 'एक भारत श्रेष्ठ' भारत की सर्वोच्च अभिव्यक्ति होगी।

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जनजातीय समुदाय तेजी से आगे बढ़ रहा तथा देश के विकास में अपना योगदान दे रहा: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 15 नवम्बर, 2025 को जनपद सोनभद्र में धरती आबा भगवान बिरसा मुण्डा की 150वीं जयन्ती 'जनजातीय गौरव दिवस' के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुण्डा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में उन्होंने जनपद के सर्वांगीण विकास को समर्पित 548 करोड़ रुपये की 432 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व चेक वितरित किए। उन्होंने मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला पुलिस कर्मियों के लिए 25 स्कूटी को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया तथा सोनभद्र के पर्यटन पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री जी ने जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने जनजातीय समुदाय को उसके अधिकार दिलाने का कार्य किया है। प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय गौरव के संरक्षण के लिए बलरामपुर के इमलिया कोडर में जनजातीय म्यूजियम और छात्रावास की स्थापना की गयी है। शीघ्र ही मिर्जापुर मण्डल में भी म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। इससे जनजातीय गौरव की धरोहर सभी के लिए एक प्रेरणा बनेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमें जनजातीय गौरव दिवस के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। सोनभद्र के सलखन फॉसिल्स पार्क में 140 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके माध्यम से दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आध्यात्मिक दृष्टि से जनपद में शिवद्वार, पंचमुखी महादेव, कंटाकोट महादेव, ज्वालामुखी शक्तिपीठ, मुखा फॉल व हाथी नाला आदि जैसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं। यहां पर बायो डायवर्सिटी पार्क इत्यादि हैं। उत्तर प्रदेश में पायी जाने वाली 15 जनजातियों में से 14 जनजाति सोनभद्र में मिलती हैं। देश में सबसे अधिक जनजातियां सोनभद्र जनपद में ही निवास करती हैं। इनकी कुल आबादी जनपद सोनभद्र में चार लाख से अधिक है। इन सभी जनजातियों का इतिहास मानवता के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 'पी0एम0 जनमन योजना' के अन्तर्गत 'धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान' प्रारम्भ किया है। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के 517 जनजातीय ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं के साथ उनके समग्र विकास के लिए सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश की 11 लाख से अधिक जनजातीय आबादी के मध्य इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन सभी ग्रामों के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए 'वन अधिकार कानून' में संशोधन के उपरांत जनजातीय समाज के लोगों को पट्टा भी दिया जा रहा है। अब तक 23 हजार से अधिक लोगों को पट्टे आवंटित किये जा चुके हैं, जिससे जनजातीय लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक प्राप्त हुआ है और किसी भी उत्पीड़न से मुक्ति मिली है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर प्रदेश की सभी जनजातियों को सभी प्रकार की योजनाओं से आच्छादित कर रही है। सभी को भूमि का पट्टा, आवास, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, घर में शौचालय, पत्रों को वृद्धावस्था या निराश्रित महिला पेंशन आदि से आच्छादित किया जा रहा है। उनके बच्चों के लिए आंगनबाड़ी व स्कूल की व्यवस्था की जा रही है। उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना और अन्य योजनाओं से अच्छादित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में जनपद में चार पंडित दीनदयाल उपाध्याय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है, जहां आवासीय पठन-पाठन, निःशुल्क पुस्तक, पुस्तकालय, वस्त्र, स्मार्ट क्लासेस आदि की व्यवस्था के माध्यम से जनजातीय छात्र-छात्राओं को आधुनिक शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। जनपद सोनभद्र के सभी विकास खण्डो में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इनमें कक्षा 06 से कक्षा 12 तक छात्राएं एक ही परिसर में आवासीय सुविधा के साथ पठन-पाठन कर सकती हैं। अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से जनजातीय छात्रों को नीट व आई0आई0टी0 जैसी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिरसा मुण्डा के संदेश के अनुरूप जनजातीय समाज को राष्ट्रप्रथम के भाव से जोड़ने के लिए सोनभद्र के जनजातीय युवाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। सरकार द्वारा जनजातीय समाज के अनुभवी वैद्यों की विशेषज्ञताओं और उनकी जड़ी बूटी औषधियों को प्रचारित करने का कार्य किया जा रहा है। इससे उनको अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद सोनभद्र में 3,394 करोड़ रुपये लागत से निर्मित कनहर सिंचाई परियोजना के माध्यम से रॉबर्ट्सगंज, दुद्धी व ओबरा विधानसभा के 108 ग्रामों के 53 हजार से भी अधिक कृषक परिवारों को 35 हजार 467 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। जनजातीय ग्रामों में 'हर घर नल योजना' का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। पूर्ण संतृप्तीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जनपद में प्रदेश एवं केंद्र सरकार की योजनाओं से हुए विकास सुविधाओं में बढ़ोत्तरी आये परिवर्तन की चर्चाएं भी कीं।

दीक्षांत समारोह भारत की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के समावर्तन समारोह का परिवर्तित रूप: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 17 नवम्बर, 2025 को यहां बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, लखनऊ के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। दीक्षान्त समारोह का शुभारम्भ करने के उपरान्त मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को मेडल तथा उपाधियां प्रदान कीं।

इस अवसर पर सम्बोधित करते हुएमुख्यमंत्री जी ने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और कहा कि दीक्षान्त समारोह आपके जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहां प्राप्त शिक्षा का उपयोग आप भविष्य में कर सकेंगे। यह केवल पासआउट बैच का दीक्षांत समारोह नहीं, बल्कि इण्डिया ट्रान्सफॉर्मिंग जनरेशन का उदाहरण है। उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की विजनरी लीडरशिप में भारत के विकास को नई गति मिलेगी। दीक्षांत समारोह भारत की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के समावर्तन समारोह का परिवर्तित रूप है। भारत की प्राचीन परम्परा में शिक्षा पूर्ण कर जब कोई स्नातक गुरुकुल से बाहर निकलता था, तब कुलगुरु द्वारा विद्यार्थी को दीक्षा उपदेश दिया जाता था।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत के गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण कर जब कोई स्नातक बाहर निकलता था, तब भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित पाता था। भारत उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। दुनिया भारत का अनुसरण करती थी। जब हम दुनिया का अनुसरण करने लगे, तो हमारी ताकत भी उसी प्रकार से कम होती गयी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाबू बनारसी दास जैसी विभूति के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा सुयोग्य राजनेता थे। स्व0 अखिलेश दास जी

ने अपने पूर्वजों की स्मृतियों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ते हुए लखनऊ में विश्वविद्यालय जैसा संस्थान स्थापित किया। उनके प्रति श्रद्धा का भाव हमारे अन्तःकरण में होना चाहिए। बी0बी0डी0 विश्वविद्यालय ने एकेडमिक एक्टिविटिज के साथ-साथ स्पोर्ट्स को भी जोड़ते हुए विभिन्न कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विगत 11 वर्षों से चल रही भारत की विकास यात्रा को पूरा विश्व अंगीकार कर रहा है। प्रत्येक भारतवासी को इस विकास यात्रा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। लोगों में व्याप्त हताशा और निराशा को आशा और उत्साह में बदलने का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2014 के बाद भारत ने छोटे-छोटे प्रयोग कर उसके सकारात्मक परिणाम दुनिया के सामने लाया है। प्रधानमंत्री जी ने सकारात्मक दृष्टि अपनाते हुए प्रत्येक गरीब के जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट खुलवाये। उसके बाद 'डिजिटल इण्डिया मिशन' के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में प्रदान किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत लगभग 50 करोड़ लोग विभिन्न योजनाओं से आच्छादित हुए हैं। डिजिटल पेमेण्ट के माध्यम से आज समस्त योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में प्रदान किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया मिशन के साथ-साथ युवाओं के लिए स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इण्डिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इससे युवाओं की आकांक्षाओं को नये पंख मिले हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बी0बी0डी0 यूनिवर्सिटी स्केल और स्किल के बेहतरीन समन्वय का केन्द्र बिन्दु है।मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बी0बी0डी0 यूनिवर्सिटी स्केल और स्किल के बेहतरीन समन्वय का केन्द्र बिन्दु है।प्रदेश ने ए0आई0 के डाटा सेंटर, इमेजिंग टेक्नोलॉजी तथा रोबोटिक ड्रोन टेक्नोलॉजी के हब के रूप में स्वयं को स्थापित किया है। बी0बी0डी0 विश्वविद्यालय इमेजिंग टेक्नोलॉजी को अपना पार्ट बनाए। यहां शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्रारम्भ किये जाएं। तीन माह, छह माह तथा एक वर्ष के सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक ए0आई0 के क्षेत्रों में कार्य प्रारम्भ किये जाएं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी जॉब कट नहीं करती, बल्कि नए अवसर प्रदान करती है। वर्ष 1990 के दशक के प्रारम्भ में कंप्यूटर के प्रचलन से रोजगार कम नहीं हुए, बल्कि विभिन्न सेक्टरों में रोजगार के नये अवसर उत्पन्न हुए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बी0बी0डी0 संस्थान युवाओं को टेक्नोलॉजी के साथ-साथ संस्कारों से भी जोड़े, जिससे विकसित भारत का निर्माण किया जा सके।

फॉरेन्सिक लैब मॉडर्न पुलिसिंग के लिए गेम चेंजर साबित होगी : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 18 नवम्बर, 2025 को जनपद गोरखपुर में 72.78 करोड़ रुपये की लागत से क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के नवीन उच्चीकृत भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने प्रयोगशाला का भ्रमण कर जांच की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में डाटा स्टोरेज (मोबाइल, लैपटॉप, सी0सी0टी0वी0 आदि) एवं रिकवरी, आवाज मिलान सम्बन्धी जांच, फॉरेन्सिक सिद्धांतों के इन्जीनियरिंग में उपयोग, अपराध सम्बन्धी झूठ पकड़ने, विस्फोटक पदार्थ एवं आग्नेयास्त्र (बुलेट) सम्बन्धी जांच की जा सकेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला के रूप में एक नई सौगात प्राप्त हुई है। वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में भारत सरकार ने देश में 03 नये कानून लागू किये, जिनकी अवधारणा प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को समय से न्याय देने की है। ब्रिटिश कालखण्ड की दण्ड पर आधारित अवधारणा से हटकर प्रत्येक व्यक्ति को समय पर न्याय दिलाने की दृष्टि से गत वर्ष जुलाई में भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 को लागू किया गया, जिसमें यह व्यवस्था की गयी कि जिन अपराधों में 07 वर्ष से ऊपर की सजा है, उनमें फॉरेन्सिक साक्ष्य जुटाये जाएगें।

नये कानूनों के लिए प्रदेश सरकार ने पहले से ही तैयारी की थी। पहले अपराधी अपराध करता था, अपराध के बाद साक्ष्य एकत्रित किये जाते थे, तो अपराधी को सजा इसलिए नहीं हो पाती थी, क्योंकि अच्छी लैब नहीं थी। लैब के अभाव में सही जांच नहीं हो पाती थी, जिससे अपराधी बच जाता था।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 में देश की सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में मात्र 04 लैब थीं। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने कमिश्नरी स्तर पर एक-एक विधि विज्ञान प्रयोशाला की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सरकार के प्रयासों से विगत 08 वर्षों में लैब की संख्या बढ़कर 12 हो गयी है। प्रत्येक कमिश्नरी में एक लैब की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 06 अन्य लैब को स्वीकृति दी गयी है, जो निर्माणाधीन हैं। इस लैब में सभी प्रकार के फॉरेन्सिक से जुड़े हुए पहलुओं की जांच की जा सकेगी, जिससे अपराधी के खिलाफ ठोस साक्ष्य ससमय न्यायालय में प्रस्तुत कर उसे दण्डित करवाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने की इस अवधारणा पर आधारित यह व्यवस्था सम्पूर्ण प्रदेश में लागू की गयी है। प्रत्येक जनपद में साक्ष्य एकत्रित करने के लिए दो-दो मोबाइल फॉरेन्सिक वैन उपलब्ध करायी गयी हैं। अब अपराध होने के कुछ ही घंटे में अपराधी के विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य होंगे। पहले दुष्कर्म, आतंकवाद तथा मर्डर आदि की घटनाएं होती थीं, तो बैलेस्टिक जांच में बहुत समय लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पायेगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गोरखपुर की इस लैब में डी0एन0ए0 जांच की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है। अब कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं पायेगा। गोरखपुर की इस ए-श्रेणी की अपग्रेड लैब में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी। यहां तेजी से, सटीक और पुख्ता साक्ष्य आधारित जांच होगी। यह फॉरेन्सिक लैब मॉडर्न पुलिसिंग के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इसका लाभ प्रदेश के सभी लोगां को प्राप्त होगा। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के नागरिकां को समय से न्याय दिलाने हेतु वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध करवाकर न्यायालय के माध्यम से अपराधी को समय से सजा दिलाई जा सकेगी।

उत्तर प्रदेश के युवाओं को फॉरेन्सिक तकनीक के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश की राजधानी में यू0पी0 स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ फॉरेन्सिक साइन्सेज स्थापित किया गया है, जिसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा तथा डिग्री के अलग-अलग प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित हैं। यह वर्तमान समय में नये प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए तकनीक के माध्यम से वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध कराकर, अपराधी को समय पर सजा दिलाने और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का हिस्सा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ फॉरेन्सिक साइंसेस एक अत्याधुनिक इन्स्टीट्यूट है, जिसमें लोगां को एडवांस डी0एन0ए0 डायग्नोस्टिक सेन्टर, वर्ल्ड क्लास डी0एन0ए0 लैब, ए0आई0, ड्रोन एण्ड रोबोटिक लैब और नैनो ड्रोन से लेकर 40 किलोग्राम वजन ले जाने में समर्थ ड्रोन के कार्यक्रम भी सरकार द्वारा संचालित किये गये हैं।

प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक मण्डल में अत्याधुनिक विधि विज्ञान प्रयोशाला की व्यवस्था की जाए तथा साइबर फॉरेन्सिक को ग्लोबल मानक तक पहुंचाया जाये। यह डी0एन0ए0 परीक्षण की क्षमता को कई गुना बढ़ाने और क्राइम साइंस मैनेजमेंट को पूरी तरह वैज्ञानिक बनाने की दिशा में सरकार के द्वारा किये जाने वाले प्रयासों तथा अपराध एवं अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति का हिस्सा है

प्रदेश के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों को समयबद्ध सिंचाई उपलब्ध कराने की दिशा में नई स्वीकृत परियोजनाएं महत्वपूर्ण : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 19 नवम्बर, 2025 को यहां लखनऊ में उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में प्रदेश में नहर व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 95 नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों को समयबद्ध सिंचाई उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगी। कुल 39453.39 लाख रुपये लागत वाली इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 36 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित होगी, जिससे लगभग 09 लाख किसानों और ग्रामीण आबादी को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। साथ ही, 273 हेक्टेयर विभागीय राजकीय भूमि को संरक्षित किया जा सकेगा। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी स्वीकृत कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण हों और गुणवत्ता पर किसी भी स्थिति में समझौता न किया जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि नहर पुनर्स्थापना से जुड़ी इन 95 परियोजनाओं में नहर प्रणाली के गैप्स में नहर निर्माण, हेड रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर, साइफन, फॉल तथा अन्य पक्की संरचनाओं का निर्माण सम्मिलित है। नहरों के आन्तरिक एवं बाह्य सेक्शन के सुधार, फिलिंग रीच में लाइनिंग के कार्य, क्षतिग्रस्त कुलाबों के पुनर्निर्माण, नहरों पर पुल-पुलियों के निर्माण एवं मरम्मत तथा नहर पटरियों पर खड़न्जा निर्माण को भी परियोजनाओं में सम्मिलित किया गया है।

निरीक्षण भवनों, कार्यालय भवनों तथा नहरों पर निर्मित पनचक्कियों के जीर्णोद्धार के साथ ही विभागीय भूमि की सुरक्षा हेतु बाउन्ड्रीवाल निर्माण भी प्रस्तावित है। परियोजनाओं के क्रियान्वयन से सिंचाई नेटवर्क की क्षमता बढ़ेगी और विभिन्न क्षेत्रों में जल उपलब्धता सुनिश्चित होगी, विशेष रूप से पूर्वांचल, तराई, बुन्देलखण्ड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को इनसे बड़ा लाभ मिलने की सम्भावना है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल निर्माण नहीं बल्कि जल प्रबन्धन की दक्षता, किसान हित, कृषि उत्पादन वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के किसी भी किसान की फसल सिंचाई के अभाव में प्रभावित न होने पाए। उन्होंने बैठक में विभाग को अनुपयोगी पड़ी भूमि के सर्वेक्षण और उसके सदुपयोग हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि विभागीय भूमि का सुविचारित उपयोग विभाग की आय संवर्द्धन में सहायक होगा।

उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 14 नवंबर, 2025 को लोक भवन लखनऊ में आई0सी0सी0 महिला विश्व कप-2025 की विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य सुश्री दीप्ति शर्मा ने शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 14 नवम्बर, 2025 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

- मंत्रिपरिषद ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वृद्धजनों का 'एक परिवार एक पहचान' फैमिली आई0डी0 प्रणाली से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत स्वतः नामांकन एवं स्वीकृति कर भुगतान किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

- मंत्रिपरिषद ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश की समस्त चीनी मिलों (सहकारी क्षेत्र, निगम एवं निजी क्षेत्रों) द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ने के 'राज्य परामर्शित मूल्य (एस0ए0पी0)' के निर्धारण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।इसके अन्तर्गत गन्ना कृषकों को उनकी उपज का समुचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से पेराई सत्र 2025-26 हेतु गन्ने की अगेती प्रजातियों के लिए 400 रुपये प्रति कुन्तल, सामान्य प्रजातियों के लिए 390 रुपये प्रति कुन्तल तथा अनुप्रयुक्त प्रजातियों के लिए 355 रुपये प्रति कुन्तल का मूल्य निर्धारित किया गया है।

  इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि पेराई सत्र 2025-26 हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित किये गये 'राज्य परामर्शित मूल्य (एस0ए0पी0)' के अनुसार देय गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा कृषकों को एकमुश्त किया जाए। पेराई सत्र 2025-26 के लिए चीनी के बाह्य क्रय केन्द्रों से गन्ने का परिवहन मिल गेट तक कराए जाने के मद में होने वाली ढुलाई कटौती की दर 60 पैसे प्रति कुंतल प्रति किलोमीटर, अधिकतम 12 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित की जाए। गन्ना कृषकों एवं सहकारी गन्ना विकास समितियों के हितों के दृष्टिगत पेराई सत्र 2025-26 हेतु गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों को देय अंशदान की दर 5.50 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित की जाए एवं तद्नुसार उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के नियम-49 में आवश्यक संशोधन किया जाए।

- मंत्रिपरिषद ने 10 वर्ष तक की अवधि के किरायेदारी/पट्टा विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस में छूट दिए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-17 व 18 के प्राविधानों के अधीन एक वर्ष की अवधि की अचल सम्पत्ति की किरायेदारी सम्बन्धी विलेख का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है, बल्कि ऐच्छिक है। एक वर्ष से अधिक की अवधि की अचल सम्पत्ति की किरायेदारी सम्बन्धी विलेख का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है।

- मंत्रिपरिषद ने प्लेज योजना में संशोधन/परिवर्धन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। निर्णय के अनुसार प्लेज पार्क के लिये प्रस्तावित भूमि को 12 मीटर के स्थान पर कम से कम 07 मीटर चौड़ी सड़क से जुड़े होने का प्राविधान किया जाएगा, जिसमें कम से कम 07 मीटर ब्लैक टॉप रोड तथा कम से कम 1.50 मीटर पेवमेंट फुटपाथ आदि शामिल होंगे।

  शर्त यह होगी कि यदि सम्पर्क मार्ग की चौड़ाई 07 मीटर होगी, तो प्लेज पार्क में सिर्फ ग्रीन/ऑरेंज कैटेगरी के उद्योगों को अनुमन्यता होगी। यदि सम्पर्क मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर या अधिक होगी, तो सभी कैटेगरी के उद्योगों को अनुमन्यता होगी। यदि प्लेज पार्क का क्षेत्रफल 15 से 50 एकड़ के मध्य होगा, तो राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा प्लेज पार्क तक 2.5 किलोमीटर सड़क निर्माण कराया जायेगा।

  एम0एस0एम0ई0 विभाग द्वारा विकसित होने वाले तथा पूर्व में विकसित ऐसे सभी प्लेज पार्कों पर 25 प्रतिशत विकास शुल्क अधिरोपित किया जाएगा, जो विकास प्राधिकरणों के नोटिफाइड क्षेत्र में स्थापित एवं विकसित होंगे। नोटिफाइड क्षेत्र से बाहर विकसित होने वाले प्लेज पार्कों पर किसी प्रकार का विकास शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

  प्राधिकरण के नोटिफाइड क्षेत्रों के अन्दर विकास प्राधिकरण द्वारा ही मानचित्र स्वीकृत किये जायेंगे। बाहर के सभी क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृत करने हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग अथवा उनके द्वारा नामित प्राधिकारी अधिकृत होंगे।

  प्लेज पार्क में स्टाम्प शुल्क देयता के लिए सम्पूर्ण औद्योगिक आस्थान को एक इकाई माना जायेगा। 07 मीटर या उससे अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित औद्योगिक भू-खण्ड के मूल्यांकन हेतु एक समान सर्किल दर निर्धारित की जाएगी। प्लेज पार्क को विकसित करने के उपरान्त, जिलाधिकारी द्वारा प्लेज पार्क में स्थित भूखण्डों का मूल्यांकन करके न्यूनतम सर्किल दर निर्धारित की जायेगी। न्यूनतम दर निर्धारित करने से पूर्व, जिलाधिकारी द्वारा तत्समय समस्त हितधारक विभाग/संस्था के साथ विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जायेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 14 नवम्बर, 2025 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

- मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0 कुसुम) योजना के अंतर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर स्टैंड एलोन सोलर पंपों की स्थापना हेतु वर्ष 2024-25 के अवशेष लक्ष्यों की वर्ष 2025-26 में पूर्ति की कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के अन्तर्गत आने वाली इकाइयों को उच्चीकृत करते हुए स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश की स्थापना किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-4, 50 व 52 एवं अधिनियम की अनुसूची में संशोधन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2025 के प्रख्यापन तथा उसके प्रतिस्थानी विधेयक के आलेख पर विभागीय मन्त्री का अनुमोदन प्राप्त कर उसे राज्य विधानमण्डल में पुरःस्थापित/पारित कराये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

- मंत्रिपरिषद ने जनपद बागपत में पी0पी0पी0 मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु तहसील बागपत के ग्राम मीतली में चिन्हित मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश की कुल 5.6000 हेक्टेयर भूमि में से 5.0700 हेक्टेयर (विवादित भूमि 0.5300 हेक्टेयर को छोड़ते हुए) को सभी प्रकार के निर्बन्धनों से मुक्त कराते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

- मंत्रिपरिषद ने मा0 मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपर निजी सचिव के 156 पदों का निजी सचिव ग्रेड-1 के पदों पर किए गए उच्चीकरण एवं निजी सचिव संवर्ग के 446 पदों के विभाजन सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृत किया है।ज्ञातव्य है कि मा0 उच्च न्यायालय में मा0 न्यायमूर्तिगण के साथ केवल निजी सचिव के ही कार्य करने की विशिष्ट व्यवस्था है। मा0 उच्च न्यायालय के अधिष्ठान में मा0 न्यायाधीशगण की वर्तमान प्रभावी संख्या 135 के अनुरुप निजी सचिवों की कुल संख्या 446 होती है, जबकि अद्यतन स्वीकृत संख्या मात्र 290 है एवं 156 पदों की कमी है।वर्तमान में मा0 न्यायाधीशों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि हुयी है, अतः निजी सचिव सेवा संवर्ग की मानकानुसार आवश्यकता/अपरिहार्यता है। यह संभावित व्यय भार सीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष है।

- मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कार क्रय हेतु आसान शर्तों पर कार अग्रिम सुविधा प्रदान किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुति के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा 04.01.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कार क्रय हेतु आसान शर्तों पर कार अग्रिम प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।
  वर्तमान में पद्मनाभन समिति की संस्तुतियों के क्रम में शासनादेश दिनांक 16.10.2010 द्वारा न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को 08 लाख रुपये का कार अग्रिम अनुमन्य है। द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों को अब 10 लाख रुपये अथवा क्रय किए जाने वाले वाहन का मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, के बराबर कार अग्रिम स्वीकृत किया जाएगा। इस पर 05 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

- मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इस संशोधन के माध्यम से लेखपाल के 02 प्रतिशत पदों पर योग्य एवं अनुभवी कार्मिकों की पदोन्नति किये जाने हेतु मौलिक रूप से नियुक्त चैनमैन (चतुर्थ श्रेणी) में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, को चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

- मंत्रिपरिषद ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर बनाये जाने, दुकान तथा वाणिज्य प्रतिष्ठानों को अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक अवसर प्रदान करने एवं 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के अन्तर्गत प्रदेश में व्यवसाय अनुकूल वातावरण बनाये जाने हेतु उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 की धारा 01, 02, 03, 04ख, 06, 22, 28क, 33 एवं 35 में संशोधन हेतु उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान संशोधन अध्यादेश, 2025 के प्रख्यापन तथा उसके प्रतिस्थानी विधेयक पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर, उसे राज्य विधानमण्डल में पुरःस्थापित/पारित कराये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के प्राविधानों को नगरीय सीमाओं से बढ़ाकर सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक प्रतिष्ठान आच्छादित हो सकें। इससे हर श्रमिक को समुचित संरक्षण प्रदान किया जा सकेगा। इस अधिनियम को 20 अथवा 20 से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू किया जा रहा है। इससे छोटे प्रतिष्ठान आर्थिक क्रिया को तीव्र कर सकेंगे और प्रदेश में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। कर्मकार एवं नियोक्ता के हितों के संवर्धन से प्रदेश में व्यावसायिक व आर्थिक क्रिया में वृद्धि होगी, जिससे रोजगार का सृजन होगा।

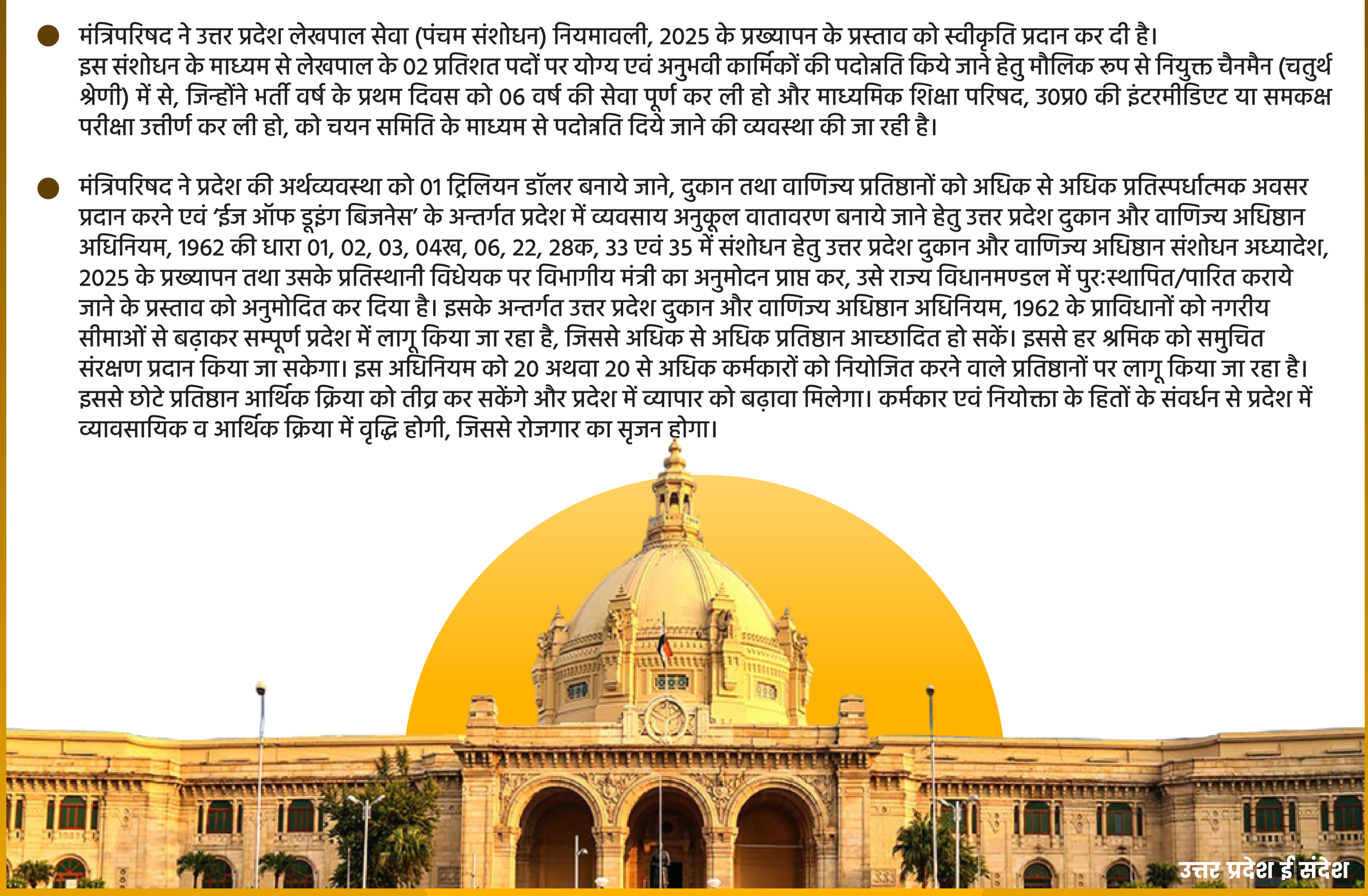

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए निदेशक श्री विशाल सिंह, आईएएस द्वारा प्रकासित